भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 369

उत्तर देने की तारीख 02 जनवरी, 2026

13 माघ, 1947 (शक)

2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली

369. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की संभावित बोली और विशेषरूप से संभावित मेजबान राज्यों या शहरों की पहचान या सिफारिश के संबंध में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के साथ कोई परामर्श किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त खेलों की मेजबानी के लिए सरकार द्वारा किसी विशेष राज्य या शहर का प्रस्ताव, सिफारिश या समर्थन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हरियाणा राज्य, अपने उत्कृष्ट खेल रिकॉर्ड और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत की पदक तालिका में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, 2036 ओलंपिक खेलों के किसी भी वर्ग के लिए स्थल या सह - मेजबान के रूप में विचाराधीन है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या प्रस्तावित ओलंपिक बोली के संबंध में सरकार द्वारा किसी राज्य में किसी नई खेल बुनियादी ढांचा परियोजना या स्टेडियम को मंजूरी दी गई है, शुरू किया गया है या योजना बनाई गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की रूपरेखा के अनुरूप ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए औपचारिक बोली लगाने हेतु जिम्मेदार है।

2036 ओलंपिक खेलों के संबंध में, बोली अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भावी मेजबान आयोग के साथ "निरंतर संवाद" चरण में है। 2036 ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान चयन प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की वेबसाइट https://www.olympics.com/ioc/becoming-an-olympic-games-host/the-process-to-elect-olympic-hosts पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। गुजरात सरकार ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के इरादे का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(च): खेल अवसंरचना और खेल सुविधाओं का संवर्धन एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। खेल राज्य का विषय होने के कारण, खेल अवसंरचना और सुविधा के निर्माण और उसके विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। मंत्रालय के खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेल अवसंरचना/सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा रही है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत मंत्रालय द्वरा प्रदत्त सहायता से राज्यों में बनाए गए/विकसित बुनियादी खेल अवसंरचनाओं का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in. पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है:

इसके अलावा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश भर में खेलों के विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करता है। इन स्कीमों का विवरण मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। (www.yas.nic.in/sports: www.sportsauthorityofindia.nic.in:)

*****